अध्याय 2

राज्य अर्थव्यवस्था

1. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे भरोसेमंद पैमाना रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्ववर्ती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार उत्पादन लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी की घोषणा करती रही है। जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने संशोधन में उत्पादन लागत पर जीडीपी को सकल मूल्य संवर्धन–जीवीए बुनियादी मूल्यो पर और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद–जीडीपी कहा जाता है। यह मध्यवर्ती उपभोग (आउटपुट के आगे उत्पादन में प्रयुक्त और अंतिम उपभोग में प्रयुक्त नहीं) का मूल्य घटा कर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य है। उत्पादन लागत, प्राथमिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निवल उत्पादन (उत्पादन कर में से उत्पादन सब्सिडी घटाकर) कर और निवल उत्पाद करों (उत्पाद कर में से उत्पाद सब्सिडी घटा कर) के बीच के अंतर पर आधारित होता है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति उत्पादन के संदर्भ में की जाती है और यह भू–राजस्व, स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क जैसे उत्पादन वाल्यूम से पृथक होता है। दूसरी तरफ उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति प्रति यूनिट या प्रति उत्पाद किया जाता है, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, जीएसटी, बिक्री कर, निर्यात और आयात शुल्क इत्यादि। उत्पादन लागत में केवल उत्पादन के विभिन्न घटकों को किया गया भुगतान शामिल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर शामिल नहीं होता। बाजार मूल्यों तक पहुंचने के उद्देश्य से हमें उत्पादन लागत में कुल सब्सिडी को घटा कर कुल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होगा। प्राथमिक मूल्य इनके बीच निर्धारित होता है : इनमें उत्पादन कर (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर) शामिल होते हैं लेकिन उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर) शामिल नही होते। इसलिए मार्केट मूल्य निर्धारित करने के लिए हमें उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी घटा कर) को प्राथमिक मूल्यों में जोड़ना होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय/राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय प्राथमिक मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन–जीवीए/जीएसवीए जारी करता है। इसलिए इसमें निवल उत्पादन कर शामिल होते हैं, लेकिन निवल उत्पाद कर शामिल नहीं होते। जीडीपी/जीएसडीपी (बाजार मूल्यों पर) के निर्धारण के लिए हमें प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए में निवल उत्पाद कर जोड़ने होते हैं। इसलिए

उत्पादन लागत पर जीवीए+निवल उत्पादन कर =प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर = बाजार मूल्यों पर जीडीपी।

1.1 राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी), किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे राज्य की आय भी कहा जाता है। एसडीपी की गणना या आकलन हमेशा मौद्रिक संदर्भ में की जाती है और यह प्रति व्यक्ति आय की गणना में प्रयुक्त होती है। राज्य की आर्थिक समृद्धि के मापन और अर्थव्यवस्था में आ रहे संरचनात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए यह संकेतक का काम करता है। किसी समयावधि में एसडीपी आकलन आर्थिक विकास के स्तर पर बदलावों की सीमा और दिशा स्पष्ट करता है। सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) की संरचना अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में विभिन्न सेक्टरों की सापेक्ष स्थिति का अंदाजा उपलब्ध कराती है। जो न केवल अर्थव्यवस्था में हो रहे वास्तविक संरचनात्मक

बदलावों को इंगित करता है बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने में भी सहायक होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की आय का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, जो भारतीय संघ के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के लिए विकास इंजन माना जाता है।

2. अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का असर और क्रमिक सुधार

2.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कोविड–19 का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी और पृथकवास उपायों के कड़ाई से पालन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दिल्ली महामारी रोग, कोविड–19 विनियमन, 2020 जारी किया और पूरे रा.रा.क्षे. में सोमवार 23 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे से मंगलवार 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित किया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को 21 दिन का सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया और बाद में इसे बढ़ा कर 31 मई 2020 तक कर दिया गया। भारत ने महामारी के आरंभिक चरण में मार्च से अप्रैल 2020 तक राष्ट्रव्यापी सख्त पूर्णबंदी लागू की। इसके बाद चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन में छूट दी गई और रोकथाम उपायों में कुछ ढील दी गई।

2.2 अप्रैल–मई, 2021 में देश में कोविड–19 की दूसरी लहर आई जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई, 2021 को डेल्टा वैरिएंट का नाम दिया और उसे कोविड के प्रमुख वैरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया, जो विश्वभर में फैल रहा था। डेल्टा पूर्ववर्ती संक्रमण की तुलना में तेज़ी से फैला और इससे दुनिया में ज़्यादा लोग चपेट में आए और मौतें भी ज्यादा हुई। दिसंबर, 2021 और जनवरी, 2022 के दौरान ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट के साथ देशभर में कोविड–19 की तीसरी लहर आई। इससे 2021–22 के दौरान आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ गई।

2.3 पिछले तीन साल कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। वर्ष 2020, 2021 और 2022 में नए कोविड–19 वायरस के साथ बेजोड़ उथल–पुथल देखी गई और नतीजतन महामारी एक इस सदी में आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरी। महामारी अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग पर अपने व्यापक प्रभाव के कारण विशिष्ट रही है। महामारी ने अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित किया है।

2.4 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपनाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का भारी आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि इनके कारण लगभग पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गईं, उपभोग और इन्वेस्टमेंट पर अंकुश लग गया और साथ ही श्रम की आपूर्ति और उत्पादन में रुकावट आई। इस प्रकार कोविड–19 ने पूरे विश्व के लोगों का ''जीवन'' और ''आजीविका'' बचाने के कठिन संकट में डाल दिया, क्योंकि संक्रमण की वक्र रेखा को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की वक्र रेखा और गहरी कर दी।

2.5 ये महामारी एक जबरदस्त आर्थिक आघात के रूप में सामने आई, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों को आघात पहुंचाया। बढ़ती हुई अनिश्चितता, कम होता भरोसा, आय में कमी, विकास की दुर्बल संभावनाएं, संक्रमण का भय, सभी प्रकार की संपर्क संवेदनशील गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण व्यय विकल्पों में कमी, एहतियातन बचत करने की विवशता, व्यवसायों के बंद होने का जोखिम और इसके कारण उपभोग और निवेश में गिरावट से मांग पक्ष को भारी आघात पहुंचा। आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने और श्रमिकों की आवाजाही पर पाबंदी से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा। आपूर्ति पक्ष में पहले क्रम के व्यवधान ने

मांग और आपूर्ति, दोनों पर दूसरे दौर का भी नकारात्मक असर डाला। आपूर्ति पर आरंभिक आघात के कारण पारिश्रमिक और आय में कमी आने से आगे भी समग्र मांग पर असर पड़ने और उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है, जिससे आगे फिर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। टीकाकरण से मृत्यु दर काफी हद तक कम करने में सफलता मिली, आर्थिक, गतिविधियां फिर शुरू करने का हौंसला और दूसरी लहर से आई क्रमिक आर्थिक मंदी से उत्पादन में कमी रोकने में मदद मिली।

2.6 2020–21 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी में (स्थिर मूल्यों पर) 8.96 प्रतिशत का संकुचन कोविड–19 महामारी और उसे नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों के विशिष्ट प्रभाव को दर्शाता है। जबकि, प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 2022–23 में वास्तविक जीएसडीपी का 7.85 प्रतिशत विस्तार होने की उम्मीद है, जबकि 2020–21 के संकुचन के बाद वर्ष 2021–22 के लिए दूसरे संशोधित अनुमानों के अनुसार 8.76 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर बहाल हो गई थीं। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बाद 7.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर के जीवीए/जीडीपी की तुलना में दिल्ली के जीएसवीए/जीएसडीपी में देखी गई वृद्धि की क्षेत्रवार स्थिति विवरण 2.1 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 2.1
अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
1. कृषि, वानिकी और मछली पालन	-2.30	6.2	-19.04	4.1	-8.88	3.5	0.51	4.0	4.61	1.8
2. खनन और खुदाई	9.49	-3.0	12.75	-8.6	-32.04	7.1	-22.41	4.6	9.34	8.1
3. विनिर्माण	4.96	-3.0	0.05	2.9	11.44	11.1	0.57	1.3	4.49	6.5
4.बिजली, गैस, जल आपूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं	-6.20	2.3	-4.98	-4.3	9.63	9.9	-0.93	9.0	6.19	8.3
5. निर्माण	-2.19	1.6	-6.47	-5.7	23.38	14.8	12.10	10.0	7.46	10.7
6.व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	5.67	6.0	-24.44	-19.7	8.37	13.8	13.93	14.0	9.22	6.3
7.वित्तीय, जायदाद (संपत्ति), और पेशेवर सेवाएं	3.62	6.8	-0.60	2.1	6.74	4.7	5.64	7.1	5.44	8.9
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	10.44	6.6	-3.90	-7.6	6.90	9.7	9.50	7.2	9.66	7.7
जीएसवीए/जीवीए बुनियादी मूल्यों पर	**4.79**	**3.9**	**-7.99**	**-4.2**	**7.06**	**8.8**	**7.48**	**7.0**	**7.19**	**6.9**
जीएसडीपी/जीडीपी बाजार मूल्यों पर	**3.69**	**3.9**	**-8.96**	**-5.8**	**8.76**	**9.1**	**7.85**	**7.2**	**7.39**	**7.3**

2.7 बड़े पैमाने पर सफल टीकाकरण अभियान से अर्थव्यवस्था की स्थिति फिर से सामान्य होने लगी है और सेवा क्षेत्र खपत और निवेश में तेजी से सुधार के आसार बन गए हैं। कुल मिलाकर, महामारी से पहले के स्तर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। वर्ष 2021–22 और 2022–23 में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85

प्रतिशत की तीव्र रिकवरी हुई है, जो कम आधारभूत दुष्प्रभाव और अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्तियों पर आधारित है।

3. प्रचलित मूल्यों पर आकलन

3.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 792911 करोड़ रुपये आंका गया था, जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी में 6.13 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 744277 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2021–22 में यह बढ़ कर 881336 करोड़ रुपये और 2022–23 के दौरान बढ़कर 1014688 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 18.41 और 15.13 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के जीएसडीपी के 1107746 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 2019–20 के दौरान 712842 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी घट कर 657966 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.70 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु, वर्ष 2021–22 के दौरान यह बढ़कर 782570 करोड़ रुपये और 2022–23 में बढ़कर 911639 करोड़ रूपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 18.94 प्रतिशत और 16.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि दिल्ली का एनएसडीपी बढ़कर 997171 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जिसमें 2022–23 की तुलना में 9.38 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

3.2 अधिकांश शहरी अर्थव्यवस्था में हुई सामान्य प्रक्रिया की भांति ही दिल्ली में सेवा क्षेत्र में बढ़ोत्तरी का रुझान है। वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण से पता चला है कि कुछ वर्षों में मामूली उतार–चढ़ाव के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गिरावट का रुख है जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। खासकर दिल्ली में जीएसवीए के प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 1.58 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 13.09 प्रतिशत से घटकर 13.02 प्रतिशत हो गया जबकि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 83.42 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 85.40 प्रतिशत हो गया।

4. स्थिर मूल्यों पर आकलन (आधार वर्ष 2011–12)

4.1 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019–20 के दौरान 586168 करोड़ रुपये रिकार्ड किया गया था, जिसमें उससे पिछले वर्ष की तुलना में 3.69 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। 2020–21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटकर 533634 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें 8.96 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु 2021–22 के दौरान यह बढ़कर 580396 करोड़ रुपये और 2022–23 के दौरान बढ़कर 625981 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें क्रमशः 8.76 प्रतिशत और 7.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2023–24 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 672247 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2022–23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू

उत्पाद (एनएसडीपी) स्थिर मूल्यों पर 2019–20 के दौरान 522031 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 3.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी घट कर 465770 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.78 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु, वर्ष 2021–22 के दौरान यह बढ़कर 507595 करोड़ रुपये और 2022–23 के दौरान बढ़ कर 548826 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.98 प्रतिशत और 8.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली का एनएसडीपी बढ़कर 590836 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जिसमें वर्ष 2022–23 की तुलना में 7.65 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

4.2 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मामूली बदलाव को छोड़कर गिरावट का रुख रहा लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। अधिक स्पष्ट शब्दों में, दिल्ली के जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जो 2011–12 के मूल्यों (स्थिर मूल्यों) पर 2011–12 में 3.49 प्रतिशत था, वह 2023–24 में घट कर 1.64 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 13.92 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जो 2011–12 के मूल्यों पर 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था वह 2023–24 में बढ़कर 84.44 प्रतिशत हो गया।

4.3 प्रचलित मूल्यों और 2011–12 के (स्थिर) मूल्यों के आधार पर पिछले 13 वर्षों में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी विवरण 2.2 में दी गयी है।

विवरण 2.2

दिल्ली का जीएसडीपी और एनएसडीपी–प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्यों पर		एनएसडीपी बाजार मूल्यों पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011–12)	प्रचलित	स्थिर (2011–12)
1.	2011-12	343798	343798	314650	314650
2.	2012-13	391388	366628	357400	334193
3.	2013-14	443960	392908	404841	356528
4.	2014-15	494803	428355	448487	387639
5.	2015-16	550804	475623	500524	431730
6.	2016-17	616085	511765	558546	461592
7.	2017-18	677900	542015	613631	487631
8.	2018-19	738389	565327	665808	506332
9.	2019-20	792911	586168	712842	522031
10.	2020-21 *(तीसरा सं.अ)*	744277	533634	657966	465770
11.	2021-22 *(दूसरा सं.अ.)*	881336	580396	782570	507595
12.	2022-23 *(पहला स.अ.)*	1014688	625981	911639	548826
13.	2023-24 *(अ.अ.)*	1107746	672247	997171	590836

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ)–तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)–द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.स.अ.)–प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.)– अग्रिम आकलन

4.4 प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1
दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(करोड़ रुपये)

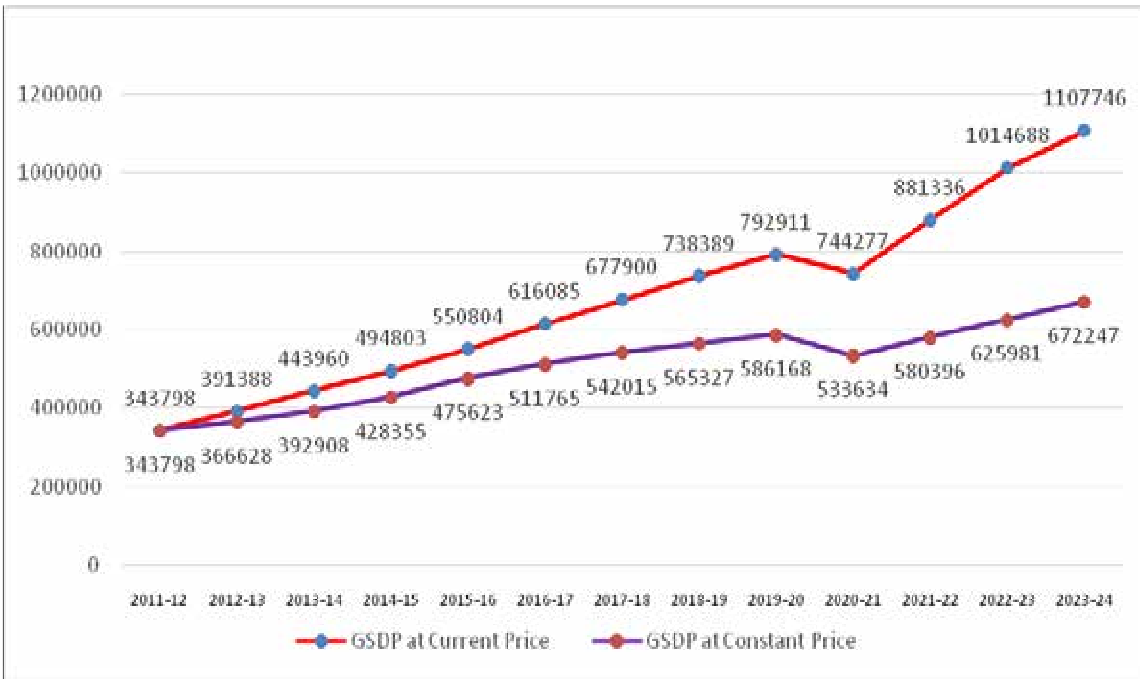

4.5 पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रचलित और 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि विवरण 2.3 में दी गयी है।

विवरण 2.3
दिल्ली का जीएसडीपी और एनएसडीपी–प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(प्रतिशत में)

क्र.स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्यों पर		एनएसडीपी बाजार मूल्यों पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011–12)	प्रचलित	स्थिर (2011–12)
1.	2012-13	13.84	6.64	13.59	6.21
2.	2013-14	13.43	7.17	13.27	6.68
3.	2014-15	11.45	9.02	10.78	8.73
4.	2015-16	11.32	11.03	11.60	11.37
5.	2016-17	11.85	7.60	11.59	6.92
6.	2017-18	10.03	5.91	9.86	5.64
7.	2018-19	8.92	4.30	8.50	3.84
8.	2019-20	7.38	3.69	7.06	3.10
9.	2020-21	-6.13	-8.96	-7.70	-10.78
10.	2021-22	18.41	8.76	18.94	8.98
11.	2022-23	15.13	7.85	16.49	8.12
12	2023-24	9.17	7.39	9.38	7.65

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

4.6 राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन की संक्षिप्त पद्धति

4.6.1 अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र धरती से उत्पादों का निष्कर्षण अथवा अर्जन करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल और बुनियादी खाद्यान्न का उत्पादन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र से सम्बद्ध गतिविधियों में कृषि (आजीविका और वाणिज्यिक दोनों), खनन, वानिकी, खेती, चारागाह, शिकार और संग्रहण, मत्स्य उद्योग और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। इस क्षेत्र से सम्बद्ध कच्चे माल की पैकेजिंग और प्रसंस्करण को भी इस क्षेत्र का हिस्सा समझा जाता है। कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग के लिए जीएसवीए के अनुमान उत्पादन पद्धति से संकलित किए जाते हैं। खनन और उत्खनन उद्योग में जीएसवीए के अनुमान गैर–विभागीय उद्यम और प्राइवेट कोर्पोरेट उद्यमों से सम्बद्ध कंपनियों के वार्षिक वित्तीय ब्यौरों से संकलित किए जाते हैं। कंपनियों के ये ब्यौरे एमसीए 21 डेटाबेस से निकाले जाते हैं, जिसके लिए उत्पादन पद्धति अपनाई जाती है।

4.6.2 अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जो उपभोग के लिए तैयार, इस्तेमाल योग्य उत्पाद बनाते हैं; जिनमें विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जलापूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से तैयार वस्तुओं का विनिर्माण करता है, या ऐसी वस्तुएं बनाता है, जो अन्य व्यवसायों द्वारा निर्यात, या घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जीएसवीए के आकलन के प्रयोजनों के लिए, समूची विनिर्माण गतिविधियों को मोटेतौर पर दो व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, ये हैं – विनिर्माण –'संगठित विनिर्माण' और 'असंगठित विनिर्माण'। संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुमानों के वास्ते गैर–विभागीय उद्यमों (एनडीई) के वार्षिक खातों, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में एमसीए डेटा बेस और अर्द्ध–निगमों के मामले में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। असंगठित विनिर्माण के अंतर्गत घरेलू उद्यम शामिल हैं। गैर–निगमित विनिर्माण उद्यमों के सकल मूल्य संवर्धन के श्रेणीवार आकलन संकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 67वें दौर (गैर–निगमित उद्यम संबंधी) के सर्वेक्षण, 2010–11 और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर (रोजगार बेरोजगारी संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011–12 के लिए प्रभावकारी श्रम लागत पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। विद्युत उप–क्षेत्र (गैर–विभागीय उद्यमों और निजी कोर्पोरेट क्षेत्र) में जीएसवीए के आकलन उत्पादन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये आकलन राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य में स्थित अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों के वार्षिक लेखों के विश्लेषण के आधार पर लगाए जाते हैं। गैस के संदर्भ में जीएसवीए के अनुमान उद्यमिता दृष्टिकोण के जरिए संकलित किए जाते हैं। जलापूर्ति के लिए जीएसवीए के आकलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं जिनमें गैर–विभागीय उद्यमों और निजी कोर्पोरेट संस्थाओं के मामले में उत्पादन पद्धति अपनाई जाती है। री–मेडिएशन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं के लिए जीएसवीए के अनुमान रीसाइकलिंग, सीवरेज और अन्य कचरा प्रबंधन सेवाओं की समग्र रूप में गणना करते हुए संकलित किए जाते हैं। समूची अर्थव्यवस्था के लिए लेखाबद्ध निर्माण के आकलन पहले वस्तु आपूर्ति दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। निजी निगमों के बारे में आकलन कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी कंपनियों के वित्तीय मानदंड के बारे में एमसीए–21 डेटा बेस द्वारा प्रदत्त जानकारी का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं।

4.6.3 तृतीयक क्षेत्र की दिल्ली के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह रोजगार क्षमता और राज्य की आय में योगदान, दोनों ही संदर्भों में अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र व्यापक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे सर्वाधिक अत्याधुनिक क्षेत्र से लेकर असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाओं तक शामिल

हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, फेरी वाले, रिक्शा चालक आदि की सेवाएं। औद्योगिक श्रेणियों के संदर्भ में, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्त्रां; परिवहन; भंडारण; संचार; वित्तीय सेवाएं; रीयल एस्टेट; रिहायशी और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन जैसे उप क्षेत्र; और शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र खंड के लिए जीएसवीए वार्षिक रिपोर्टों/खातों और बजट दस्तावेजों के आर्थिक विश्लेषण के जरिए प्राप्त किया जाता है। प्राइवेट निगमों के आकलन एमसीए–21 डेटा बेस और असंगठित खंड एनएसएस सर्वेक्षणों के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए संकलित किए जाते हैं।

5. प्रति व्यक्ति आय

5.1 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 2022–23 के दौरान 430120 रुपये पहुंच गई, जबकि 2021–22 में यह 376217 रुपये, 2020–21 में 322311 रुपये और 2019–20 में 355798 रुपये थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2023–24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर 461910 रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर पिछले 12 वर्षों (2013–24) में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.12 प्रतिशत, 10.86 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत, 9.32 प्रतिशत, 9.36 प्रतिशत, 7.70 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत, 5.04 प्रतिशत, (–) 9.41 प्रतिशत, 16.72 प्रतिशत, 14.33 प्रतिशत और 7.39 प्रतिशत रही है।

5.2 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2022–23 में स्थिर मूल्यों पर 258941 रुपये रही जबकि 2021–22 में यह 244024 रुपये थी, अर्थात् इसमें 6.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023–24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 273687 रुपये पर रहने की संभावना है। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

5.3 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक थी। पिछले 13 वर्षों में दिल्ली और समग्र भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी विवरण 2.4 में दी गयी है।

विवरण 2.4
2011–12 से 2023–24 के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

वर्ष	प्रचलित मूल्य (आधार वर्ष 2011–12)		स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12)	
	दिल्ली*	अखिल भारतीय	दिल्ली*	अखिल भारतीय
2011-12	185001	63462	185001	63462
2012-13	205568	70983	192220	65538
2013-14	227900	79118	200702	68572
2014-15	247209	86647	213669	72805
2015-16	270261	94797	233115	77659
2016-17	295558	104880	244255	83003
2017-18	318323	115224	252960	87586
2018-19	338730	125946	257597	92133
2019-20	355798	132341	260559	94420
2020-21	322311	127065	228162	86054
2021-22	376217	148524	244024	92583
2022-23	430120	172276	258941	98374
2023-24	461910	185854	273687	104550

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ)–तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)–द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.स.अ.) – प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.) – अग्रिम आकलन

** राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।*

5.4 विवरण 2.4 से यह पता चलता है कि 2011—12 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 185001 रुपये थी, जो 2023—24 में बढ़कर 461910 रुपये हो गयी, अर्थात् इसमें 8.11 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 3.46 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई। प्रचलित और स्थिर दोनों मूल्यों पर पिछले 13 वर्षों के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय संबंधी जानकारी क्रमशः चार्ट 2.2.1 और 2.2.2 में दी गयी है।

चार्ट 2.2.1

प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

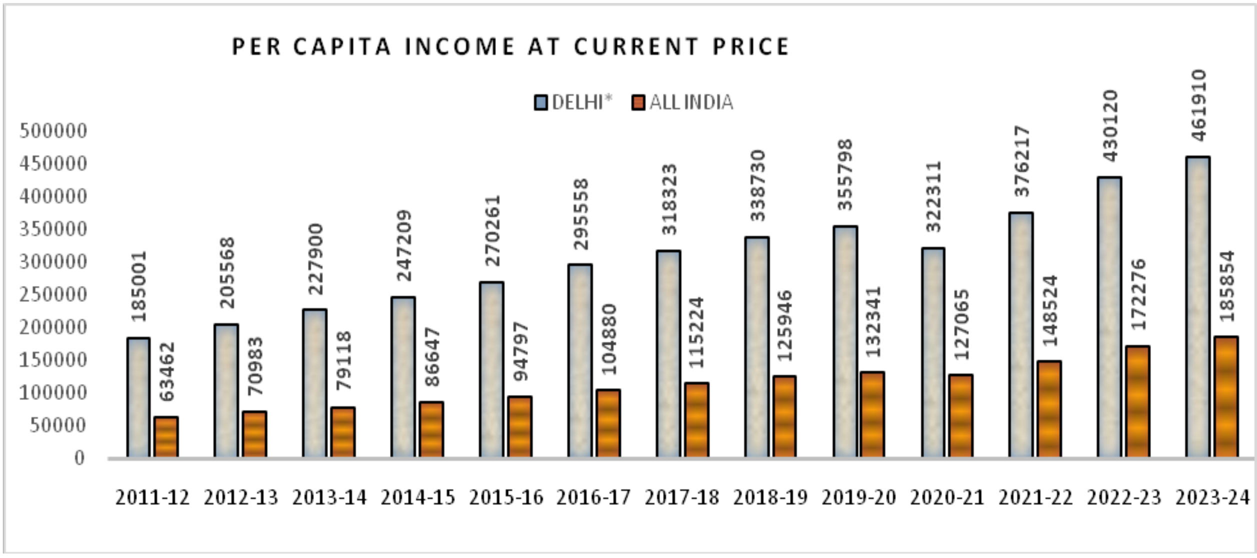

चार्ट 2.2.2

स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

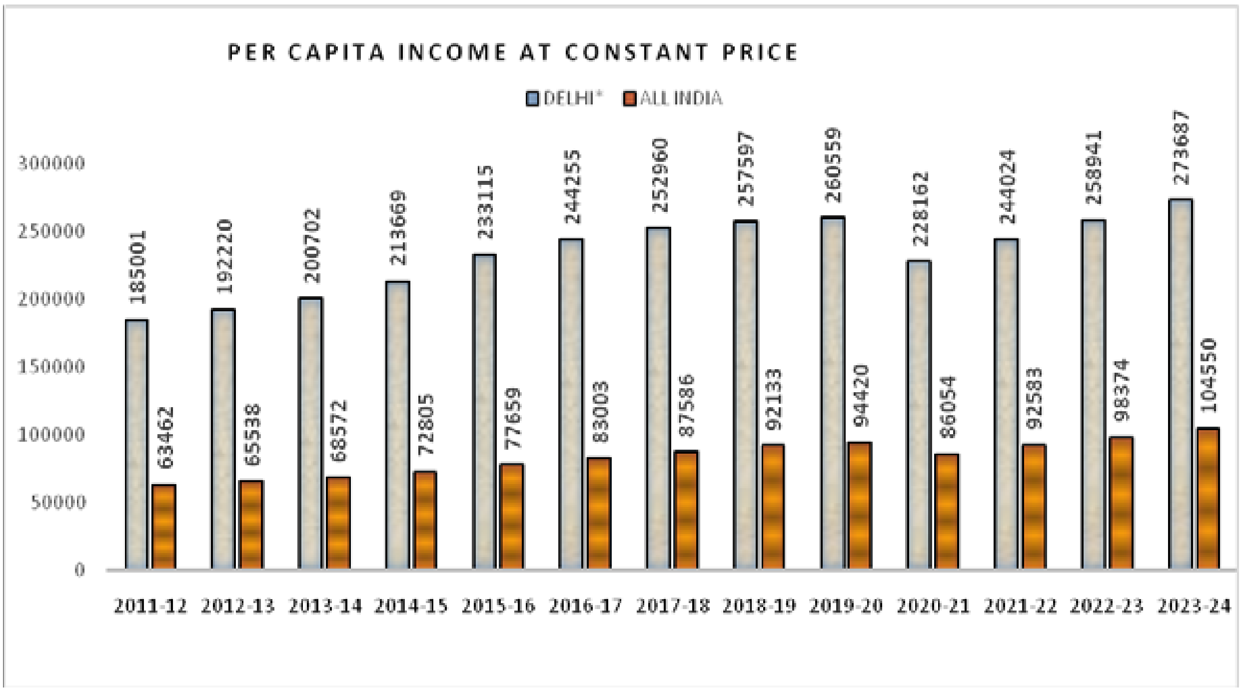

5.5 प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर विवरण 2.5 में दी गयी है।

विवरण 2.5
2012–13 से 2023–24 के बीच दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्र.स	वर्ष	दिल्ली		भारत	
		प्रचलित	स्थिर (2011–12)	प्रचलित	स्थिर (2011–12)
1.	2012-13	11.12	3.90	11.9	3.3
2.	2013-14	10.86	4.41	11.5	4.6
3.	2014-15	8.47	6.46	9.5	6.2
4.	2015-16	9.32	9.10	9.4	6.7
5.	2016-17	9.36	4.78	10.6	6.9
6.	2017-18	7.70	3.56	9.9	5.5
7.	2018-19	6.41	1.83	9.3	5.2
8.	2019-20	5.04	1.15	5.1	2.5
9.	2020-21	-9.41	-12.43	-4.0	-8.9
10.	2021-22	16.72	6.95	16.9	7.6
11.	2022-23	14.33	6.11	16.0	6.3
12	2023-24	7.39	5.69	7.9	6.3

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

6. सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

6.1 दुनिया की अधिकतर शहरीकृत क्षेत्रों में आम रुझान के अनुरूप दिल्ली की आमदनी में भी प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र का है। सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में क्षेत्रगत बढ़ोतरी के विशलेषण से भी इसी तथ्य का स्पष्ट पता चलता है। समग्र जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन शामिल है) में पिछले 13 वर्षों में मामूली विचलन के साथ गिरावट का रुझान रहा है, कुछ गौण विचलनों को छोड़कर। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मिश्रित रुझान रहा है। प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) के संदर्भ में तीन अलग अलग क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में दिल्ली के जीएसवीए की संरचना 2011–12 से 2023–24 की अवधि के लिए विवरण 2.6 मे दी गई है।

विवरण 2.6

दिल्ली में जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना (बुनियादी मूल्यों पर) – प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक		कुल	
		करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%	करोड़ रु.	%
1	2011-12								
	क. प्रचलित	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
	ख. स्थिर	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
2	2012-13								
	क. प्रचलित	10048.44	2.93	48498.08	14.17	284041.02	82.90	342587.54	100.00
	ख. स्थिर	9061.01	2.82	45118.64	14.06	266752.79	83.12	320932.43	100.00
3	2013-14								
	क. प्रचलित	12741.36	3.29	54262.39	14.07	318927.16	82.64	385930.91	100.00
	ख. स्थिर	10621.54	3.10	47802.34	13.99	283200.89	82.91	341624.77	100.00
4	2014-15								
	क. प्रचलित	12115.29	2.79	53246.72	12.26	368879.09	84.95	434241.10	100.00
	ख. स्थिर	11129.20	2.96	45154.35	12.01	319564.22	85.03	375847.77	100.00
5	2015-16								
	क. प्रचलित	9987.11	2.09	65194.32	13.62	403600.12	84.29	478781.54	100.00
	ख. स्थिर	11534.36	2.80	55107.47	13.41	344275.62	83.79	410917.45	100.00
6	2016-17								
	क. प्रचलित	9008.82	1.70	71615.66	13.48	450550.91	84.82	531175.39	100.00
	ख. स्थिर	10611.73	2.42	58147.77	13.28	369230.31	84.30	437989.81	100.00
7	2017-18								
	क. प्रचलित	9776.09	1.67	80986.80	13.80	496136.82	84.53	586899.72	100.00
	ख. स्थिर	11269.34	2.43	63186.70	13.65	388876.89	83.92	463332.93	100.00
8	2018-19								
	क. प्रचलित	13482.10	2.08	87160.20	13.45	547196.76	84.47	647839.05	100.00
	ख. स्थिर	13235.04	2.71	65940.96	13.49	409406.47	83.80	488582.47	100.00
9	2019-20								
	क. प्रचलित	13716.87	1.95	88309.93	12.54	602341.97	85.51	704368.77	100.00
	ख. स्थिर	14259.75	2.78	65837.21	12.86	431868.28	84.36	511965.23	100.00
10	2020-21								
	क. प्रचलित	12590.58	1.89	84910.15	12.73	569398.64	85.38	666899.37	100.00
	ख. स्थिर	15469.87	3.28	63682.88	13.52	391917.07	83.20	471069.82	100.00
11	2021-22								
	क. प्रचलित	13024.31	1.67	105790.55	13.59	659543.49	84.74	778358.35	100.00
	ख. स्थिर	10872.37	2.16	73187.88	14.51	420245.83	83.33	504306.08	100.00
12	2022-23								
	क. प्रचलित	14294.29	1.61	117509.55	13.20	758481.43	85.19	890285.26	100.00
	ख. स्थिर	8759.12	1.62	76323.08	14.08	456953.92	84.30	542036.12	100.00
13	2023-24								
	क. प्रचलित	15376.49	1.58	126897.06	13.02	832123.89	85.40	974397.43	100.00
	ख. स्थिर	9510.22	1.64	80859.48	13.92	490655.52	84.44	581025.22	100.00

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराराक्षे, दिल्ली सरकार।
राउंडिंग ऑफ के कारण संभव है कि जोड़ का मिलान न हो

6.2 विवरण 2.6 से पता चलता है कि 2011–12 में दिल्ली की आय में 83 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, 14 प्रतिशत से कम द्वितीयक क्षेत्र की और 04 प्रतिशत से भी कम प्राथमिक क्षेत्र की रही है। अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, जो 2011–12 में 3.49 प्रतिशत था वह 2023–24 में घटकर 1.58 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो 2011–12 में प्रचलित मूल्यों पर 83.42 प्रतिशत था जो 2023–24 में बढ़कर 85.40 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो 2011–12 में 13.09 प्रतिशत था, वह मामूली कमी के साथ 2023–24 में घटकर 13.02 प्रतिशत रह गया।

6.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित की क्षेत्रगत संरचना चार्ट 2.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.3

प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना

(प्रतिशत में)

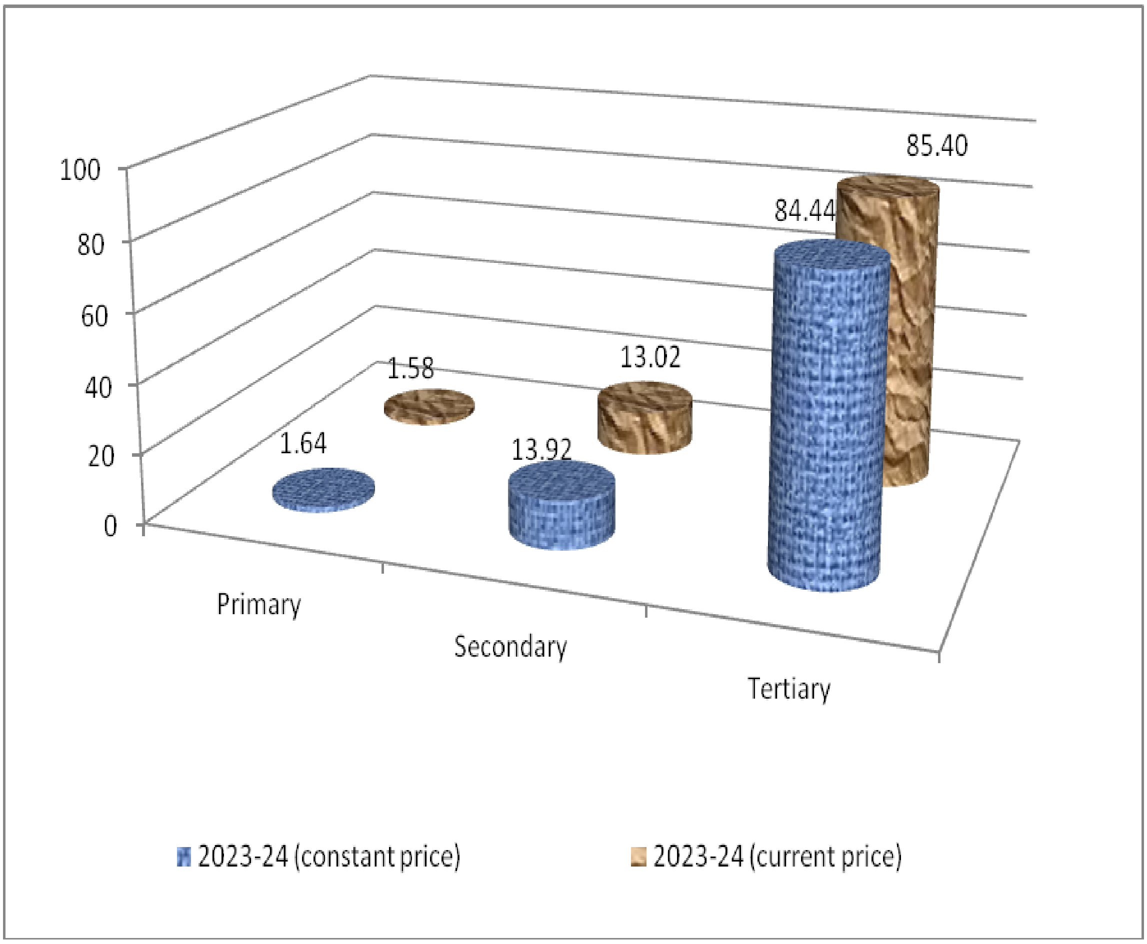

6.4 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 2.1 से तालिका 2.4 के अंतर्गत दी गयी हैं।

अध्याय एक नजर में

➢	जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने सशोधन में जीडीपी को उत्पादन लागत पर, जीडीपी को सकल मूल्य संवर्धन–जीवीए बुनियादी मूल्यों पर और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है, जो सबसे भरोसेमंद पैमाना है।
➢	उत्पादन लागत पर जीवीए+निवल उत्पादन कर =प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर = बाजार मूल्यों पर जीवीए
➢	प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था में, 2020–21 के संकुचन के बाद, 2023–24 में 7.39 प्रतिशत, 2022–23 में 7.85 प्रतिशत, 2021–22 में 8.76 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर बहाल हो गई।
➢	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के जीएसडीपी के 1107746 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के मुकाबले 9.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
➢	2023–24 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 672247 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2022–23 की तुलना में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
➢	अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023–24 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 461910 रुपये और स्थिर मूल्यों पर 273687 रुपये पर रहने की संभावना है।
➢	दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक रही है।
➢	दिल्ली के जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 1.58 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 83.42 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 85.40 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से मामूली घटकर 2023–24 में 13.02 प्रतिशत रह गया।